(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना

सं0. 18/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन० टी०)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

सा.का.नि. (अ)._____वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत निर्मित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4सी के उपनियम (2) और नियम 5 के उप नियम (5) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अंतर्गत निर्मित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम दस के उपनियम (5) और नियम 11 'के उपनियम (9) के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड मांग पत्रों को जारी किए जाने, इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में रिकॉर्ड्स का परीक्षण और डिजिटल हस्ताक्षरों द्वारा रिकॉर्ड्स और मांगपत्रों का अधिप्रमाणन हेतु निम्नलिखित शर्तों, संरक्षोपाए और प्रक्रियाओं का एतद्वारा विशेष रूप से उल्लेख करता है अर्थात्:-

1. डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक निर्धारिती भारत में प्रमाणन अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी किए गए क्लास 2 अथवा क्लास 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करेगा।
2. (i) डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक निर्धारिती कम से कम पन्द्रह दिन पहले क्षेत्राधिकार उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क को निम्नलिखित ब्यौरे सूचित करेगा:-
  - क) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रयोग हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आई डी, कार्यालय-पता और पदनाम;
  - ख) प्रमाणन प्राधिकारी का नाम;
  - ग) उक्त प्राधिकारी के पूरे पते के साथ प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि के साथ डिजिटल प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तिथि और डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता;बशर्ते कि क्षेत्राधिकारी उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त को प्रस्तुत ब्यौरों में किसी बदलाव के मामले में, ऐसे बदलाव के पन्द्रह दिन के भीतर सम्पूर्ण ब्यौरों को दोबारा प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) पहले से डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक निर्धारिती इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर उपर्युक्त ब्यौरे क्षेत्राधिकार उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित करेगा।

3. प्रत्येक निर्धारिती जो इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्डस को बनाए रखे जाने का विकल्प चुनता है और जिसके पास एक से अधिक फैक्टरी अथवा सेवा कर पंजीकरण है प्रत्येक फैक्टरी अथवा प्रत्येक सेवा कर पंजीकरण के लिए पृथक इलेक्ट्रानिक रिकार्डस बनाए रखेगा।
4. इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्डस बनाए रखे जाने का विकल्प चुनने वाला प्रत्येक निर्धारिती किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारीके अनुरोध पर दस्तावेज की प्रमाणिकता के सत्यापन हेतु एक इलेक्ट्रानिक रूप में पठनीय प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से अथवा एक विनिर्दिष्ट स्टोरेज डिवाइस पर इलेक्ट्रानिक स्वरूप और मांगपत्रों में विशिष्ट रिकार्डस प्रस्तुत करेगा और ऐसे रिकार्डस और मांग पत्र हेतु अनुरोध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पत्र अथवा ई-मेल में विनिर्दिष्ट होगा।
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार सेवा कर हेतु लागू किए गए रूप में किसी जांच पड़ताल, अन्वेषण अथवा लेखा परीक्षा के दौरान कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्डस और मांगपत्रों के प्रिन्ट आउट्स को प्रस्तुत किए जाने हेतु किसी निर्धारिती को निदेश दे सकता है और इलेक्ट्रानिक प्रारूप में इसकी शुचिता के सत्यापन के पश्चात् ऐसे रिकार्डस और मांगपत्रों के प्रिन्टआउट्स का पुनर्ग्रहण कर सकता है तथा इस संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा निर्धारिती द्वारा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में ऐसे रिकार्डस के प्रिन्ट आउट्स के पश्चात् साइन किए गए हैं यदि ऐसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो।
6. इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्डस को बनाए रखे जाने का विकल्प चुनने वाला प्रत्येक निर्धारिती सुनिश्चित करेगा कि ऐसे रिकार्डस से संबंधित वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रानिक स्वरूप में रिकार्डस के यथोचित बैक-अप को बनाए रखा और परिरक्षित किया जाता है।
7. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा०.सं०.224/44/2014-सीएक्स.6]

(रोहन)

अवर सचिव, भारत सरकार